

प्रेषक,

मनोज घन्डन,  
अपर सचिव  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संस्काक  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-२

देहरादून :

दिनांक २० मार्च, 2014

विषय:- अनुदान सं०-२७ के आयोजनागत पक्ष की केन्द्र पूरोनियानित योजना "Integrated Development of Wildlife Habitat(IDWH)" के अन्तर्गत Gangotri Wildlife Sanctuary, Govind Pashu Vihar Wildlife Sanctuary, Binsar Wildlife Sanctuary, Kedarnath Wildlife Sanctuary and Mussoorie Wildlife Sanctuary हेतु पंजीयत पक्ष के अन्तर्गत चाल वित्तीय वर्ष 2013-14 की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

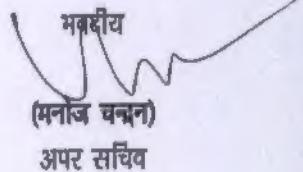
महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर प्रमुख वन संस्काक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-नि०-1232/३-६(IDWH) दि० ०३ फरवरी, 2014 के साथ संलग्न भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र सं०-१३-२४/२०१३ WL-१ दि० १३ जनवरी, 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वन विभाग के अन्तर्गत संचालित योजना "Integrated Development of Wildlife Habitat(IDWH)" योजना के पंजीयत पक्ष में भारत सरकार के पत्र में अंकित विवरणानुसार चाल वित्तीय वर्ष 2013-14 में एवं गत वर्षों के अव्ययित समायोजन सहित अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष ₹ 16,45,000/- (रु १६,४५,०००/-) (सोलह लाख पैंतीलस हजार मात्र) की धनराशि निम्न राशीं एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति भारत सरकार के पत्र सं०-१३-२४/२०१३ WL-१ दि० १३ जनवरी, 2014 द्वारा दिये गये दिशानिर्देशानुसार व्यव किया जायेगा एवं उक्त पत्र द्वारा "Integrated Development of Wildlife Habitat(IDWH)" के अन्तर्गत Gangotri Wildlife Sanctuary, Govind Pashu Vihar Wildlife Sanctuary, Binsar Wildlife Sanctuary, Kedarnath Wildlife Sanctuary and Mussoorie Wildlife Sanctuary हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार ही कार्यों का क्रियान्वयन किया जायेगा, साथ ही निर्माण कार्यों हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदित दर अनुसूची आधार पर अनुमन्य मानकों अनुसार गठित आंगणन व उस पर सक्षम स्तर से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्राविधिक, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासकीय पूर्व अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।
2. उक्त स्वीकृत व्यव चाल योजनाओं पर ही किया जाये और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय तथा विभिन्न मर्दों में व्यव से पूर्व वित अनुभाग-१ के शासनादेश सं०-२४४/XXVII(1)/2013 दिनांक ३० मार्च, २०१३ तथा शासनादेश संख्या ४१३/XXVII(1)/2013 दिनांक १० जून २०१३ द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमति/यथा स्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाय। शासन द्वारा वार्षिक सूचनायें एवं विवरण/मासिक प्रगति विवरण निर्धारित प्रारूप व समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। किसी भी शासकीय व्यव हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-१ (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनियोगन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-५ भाग-१ (लेखा नियम), आद्य-व्यवक सम्बन्धी नियम (बजट फैन्डल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्योरमेंट) नियमावली, २००८ सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. बजट प्राविधिक लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यव की अधिकतम सीमा को ही प्राप्तिकृत करता है। अतः बजट प्राविधिक से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यव किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यव भार/दायित्व सृजित किया जाय।
4. यह संज्ञान में आया है कि धनराशि विभागाध्यक्षों के निवर्तन पर रखने के उपरान्त भी विभागाध्यक्षों द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यव हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है। अतः आपके निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय, जिससे की फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
5. आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी०एम०-१७ पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा।
6. निर्धारित बी०एम०-प्रपत्र पर नियमित रूप से प्रशासकीय विभाग एवं वित विभाग को विलम्बतम ०५ तारिख तक पूर्व माह की सूचना उपलब्ध कराई जाय।
7. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यव को फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) प्रशासनिक विभाग एवं वित विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा, जिससे की राज्य स्तर पर कैश-फ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।
8. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि मजदूरी तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिये भुगतान मर्दों के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की संख्या सम्बन्धित ईकाई में समकक्ष स्तर के स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमा अन्तर्गत अथवा वित विभाग की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के अन्तर्गत ही रहेगी।
9. मानक मर्दों के आहरण प्रणाली के सम्बन्ध में शासनादेश सं०-ब-०६/X-२-२०१०-१२(11)/2009 दिनांक ३१ मार्च, २०१० द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।

- व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली हाय।
- योजनाओं की विभिन्न मर्दां पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय।
  - धनराशि का आहरण/व्यय वथा आवश्यकता ही किया जायेगा।
  - स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
  - निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का आवंटन पत्र कम्प्यूटर के माध्यम से जनरेट किया गया है एवं इसका Allotment Id S1403270291 है। आप भी अपने स्तर से अधिनस्थ आहरण अधिकारियों को कम्प्यूटर के माध्यम से online बजट आवंटन करना सुनिश्चित करेंगे।
  - निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यों की सूचना यथा आवश्यकतानुसार सुराज, भट्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1638/XXX-1-12(25)/2011, दिनांक 08 दिसम्बर, 2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वेबसाइट [www.ua.nic.in](http://www.ua.nic.in) तथा विभाग की वेबसाइट यदि कोई हो पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जाएगी और उन्हें समय समय पर अध्यावधिक किया जाएगा।
  - इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के अनुदान सं0-27 के लेखाशीर्षक 4406-बानिकी और वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय 02-पर्यावरणीय यानिकी तथा वन्य जीवन 110-वन्य जीव परिवर्कण 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 0104-“इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हेबिटेट” में मानक मर्द-24 वृहद निर्माण के नामे डाला जायेगा। इस प्रयोजन हेतु Online Budget Allotment की हार्ड कॉपी भी संलग्न की जा रही है।
  - ये आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0-173/(P)/XXVII(4)/2013, दिनांक 18 मार्च, 2014 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोपरि।

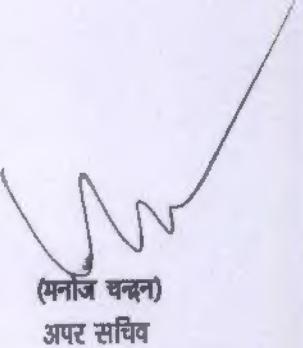


महाराष्ट्र  
(मनाज चन्दन)  
अपर सचिव

संख्या- ४२२ (1)/x-2-2014, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- संयुक्त निदेशक, WL-1 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्र सं0-13-24/2013 WL-1 द्वि 13 जनवरी, 2014 के क्रम सूचनार्थ।
- महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर मैसर्स बिल्डिंग, सहारनपुर टोड, माजरा, देहरादून।
- महालेखाकार(आईटी), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
- अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड शिविर कार्यालय-देहरादून।
- मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- मुख्य वन संरक्षक, संतकता एवं कानून प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- आयुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
- प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
- गार्ड फाइल।



(मनाज चन्दन)  
अपर सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 2013/2014

Secretary, Forest (S016)

आवंटन पत्र संख्या - 822/IX-2-2014-12(63)/2006

अनुदान संख्या - 027

ज्ञालोटमैट आई डी - S1403270291

आवंटन पत्र दिनांक - 19-Mar-2014

HOD Name - Principal Chief Conservator of Forest (4260)

1: लेखा शीर्षक	4406 - वानिकी और बन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय	02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा बन्य जीवन
	110 - बन्य जीवन परिवर्कण	01 - केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित थी
	04 - इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट औफ वाइल्ड लाईफ हैबिटेट	

Plan Voted

मानक भद्र का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	शोम
24 - बहत निर्माण कार्य	1100000	1645000	2745000
	1100000	1645000	2745000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

1645000